given to Starred Question No. 89 in the Rajya Sabha on the 23rd March, 1962, and state whether the derailment of a goods train between Mughal Sarai and Dehri-on-Sone Railway Stations was on the same section where a derailment had occurred last year?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHAH NAWAZ KHAN): NO, Sir. The derailment on 9th February, 1962 occurred on the section between Ganj Khwaja and Chandauli Majhwar stations on Eastern Railways. There was no derailment on the above section last year.

t [ALLOCATION OF EXPENDITURE ON CHAMBAL VALLEY PROJECT

चम्बल घाटी परियोजना पर होने वाले खर्च का बटवारा

***१५७. श्री विमलकुमार मन्नालाल चौरड़िया : क्या सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) चम्बल घाटी परियोजना के लिए जो कन्ट्रोल बोर्ड बनाया गया है, वह राजस्थान और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में होने वाले खर्च के बटवारे से संबंधित मामले पर कब से विचार कर रहा है; और

(ख) कुल कितना खर्च होगा और प्रत्येक राज्य कितना कितना खर्च वहन करेगा ?

*157. SHRI V. M. CHORDIA: Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state:

(a) the time since when the matter relating to the allocation of expenditure to be incurred in the Rajasthan and Madhya Pradesh areas is under consideration of the Control Board set up for Chambal Valley Project; and

(b) what will be the total expenditure and in what proportion it will be borne by each of the States?]

t[ ] English translation.

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम) : (क) चम्बल कंट्रोल बोर्ड ने इस विषय को जुलाई, १९५५ में हाथ में लिया था और इस पर सितम्बर, १९६१ तक गौर करता रहा, जब चम्बल प्रोजेक्ट पर खर्च के बटवारे के असूलों के बारे में राजस्थान और मध्य प्रदेश की दोनों सरकारों को मन्जूर फैसले किये गये ।

(ख) इस प्रोजेक्ट पर ६३·५९ करोड़ रुपये खर्च होने की उम्मीद है । दोनों राज्य जिस हिसाब से खर्च करेंगे उसकी स्टेटमेंट सभा की मेज़ पर रखी है ।

विवरण

चम्बल परियोजना पर व्यय निम्नलिखित हिसाब से राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारों द्वारा वहन होगा :

(क) गांधी सागर बांध—अनुमित लागत—१३६·२५ लाख रुपये । इसकी लागत दोनों राज्यों द्वारा बराबर बराबर बांटी जायेगी ।

(ख) कोटा बैराज.—अनुमित लागत—३८२·५५ लाख रुपये । दोनों राज्यों द्वारा बराबर अनुपात में लागत बांटी जायेगी ।

(ग) वाम तट नहर तथा उपनहरें.—अनुमित लागत—२१९·४४ लाख रुपये । सारा खर्चा राजस्थान द्वारा ही किया जायेगा ।

(घ) दक्षिण तट नहर पर राजस्थान में उपनहरें.—अनुमित लागत—२६१·०० लाख रुपये । सारा खर्चा राजस्थान द्वारा ही किया जायेगा ।

(ङ) राजस्थान में दक्षिण तट नहर.—अनुमित लागत—७८५·०९ लाख रुपये । लागत राजस्थान और मध्य प्रदेश में 'क्यूजेक्स-माइल' के आधार पर बांटी जानी है, जैसे कि

दोनों राज्य सरकारों के मुख्य अभियन्ताओं द्वारा आंकड़ों के सत्यापन के अधीन रहते हुए ७५·४० : २४·६० के अनुपात में ।

(च) मध्य प्रदेश में दक्षिण तट नहर.—अनुमित लागत—१७७४·२० लाख रुपये । सारी की सारी लागत मध्य प्रदेश के नाम डाली जानी है ।

(छ) गांधी सागर बांध विद्युत् केन्द्र.—अनुमित लागत—४७६·१२ लाख रुपये । लागत दोनों राज्यों में बराबर बराबर बांटी जानी है ।

(ज) गांधी सागर बांध से कोटा तक प्रेषण पथ.—अनुमित लागत—४०·४३ लाख रुपये । लागत दोनों राज्यों में बराबर बांटी जानी है ।

(झ) कोटा से सवाए माधोपुर तक प्रेषण पथ.—अनुमित लागत—६६·२३ लाख रुपये । लागत अन्तिम परिवर्तक क्षमताओं के अनुपातत: बांटी जानी है ।

(ट) सवाए माधोपुर से ग्वालियर तक प्रेषण पथ.—अनुमित लागत—उपलब्ध नहीं है । सारी लागत मध्य प्रदेश द्वारा वहन की जानी है ।

(ठ) राजस्थान में प्रेषण पथ.—उत्तरी ग्रिड.—अनुमित लागत—उपलब्ध नहीं है । सारी लागत राजस्थान द्वारा वहन की जानी है ।

(ड) गांधी सागर से नीमच तक प्रेषण पथ.—अनुमित लागत—२७.२८ लाख रुपये । अन्तिम परिवर्तक क्षमताओं के अनुपाततः लागत बांटी जानी है ।

(ढ) मध्य प्रदेश में प्रेषण पथ-दक्षिणी ग्रिड.—अनुमित लागत—उपलब्ध नहीं है । सारी लागत मध्य प्रदेश द्वारा वहन की जानी है ।

T[THE MINISTER OF IRRIGATIONAND POWER (HAFIZ MOHAMMAD IBRAHIM) : (a) The matter was taken up by the Chambal Control Board in / July, 1955 and engaged its attention till September 1961, when decisions mutually acceptable to the Governments of Rajasthan and Madhya Pradesh in regard to the principles of allocation of expenditure on the Chambal Project were arrived at.

(b) The total expenditure estimated to be incurred on the Project is Rs. 63-59 crores. A statement showing the proportion in which it will be borne by each of the States is laid on the Table of the House.

STATEMENT

Proportion in which expenditure on the Chambal Project will be borne by the States of Rajasthan and Madhya Pradesh is as under: —

(a) *Gandhi Sagar Dam.*—Estimated cost—Rs. 1,360-25 lakhs. Cost to be shared equally between the two States.

(b) *Kotah Barrage.*—Estimated cost—Rs. 382-55 lakhs. Cost to be shared between the two States in equal proportions.

(c) Left Bank Canal *and Distributaries.*—Estimated cost— Rs. 219-44 lakhs. Cost to be wholly debited to Rajasthan.

(d) *Distributaries in Rajasthan on Right Bank Canal.*—Estimated cost—Rs. 261.00 lakhs. Cost wholly debitable to Rajasthan.

(e) Right Bank *Canal in Rajasthan.*—Estimated cost—Rs. 785.09 lakhs. Cost to be shared between Rajasthan and Madhya Pradesh on cusec-mile basis, i.e., in the ratio of 75-40 : 24-60 subject to verification of the figures by the Chief Engineers of the two State Governments.

f[ ] English translation.

(f) *Right Bank Canal* in *Madhya Pradesh.*—Estimated cost— Rs. 1,774-20 lakhs. Cost wholly debitable to Madhya Pradesh.

(g) Gandhi. *Sagar Dam Power Station.*—Estimated cost—Rs. 479-12 lakhs. Cost to be ecpually shared between the two States.

(h) *Transmission line from* Gandhi Sagar Dam to *Kotah.*—Estimated cost—Rs. 40-43 lakhs. Cost to be shared equally between the two States.

(i) *Transmission line from Kotah to Sawai Madhopur.*—Estimated cost—Rs. 69-23 lakhs. Cost to be shared in proportion to the ultimate transformer capacities.

(j) *Transmission line from Sawai-Madhopur to Gwalior.*—Estimated cost—Not available. Entire cost to be borne by Madhya Pradesh.

(k) *Transmission lines in Rajasthan—Northern Grid.*—Estimated cost—Not available. Entire cost to be borne by Rajasthan.

(1) Transmission line from Gandhi *Sagar to Neemuch.*— Estimated cost—Rs. 27-28 lakhs. Cost to be shared in proportion to the ultimate transformer capacities.

(m) Transmission lines in Madhya *Pradesh—Southern Grid.*—Estimated cost—Not available. Cost to be wholly borne by Madhya Pradesh.]

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया: क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी स्टैटिस्टिक्स में जो रिपोर्ट दी थी उसमें ६१ करोड़ रुपये का खर्च होना बतलाया है।

हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम : यह बात मेरे इल्म में नहीं है।

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिस आधार पर सारा इस्टीमेट तैयार किया गया और यह जो आपने इस्टीमेट दिया है उसमें ट, ठ और ड पर इस्टीमेट का अनुमानित मूल्य नहीं बतलाया गया है। इसका क्या कारण है ?

हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम : आपके लफ्ज मेरी समझ में नहीं आये।

SHRI V. M. CHORDIA: I should, like to know why the hon. Minister has not given the estimated expenditure in respect of (1) Sawai-Madhopur to Gwalior electricity line, (2) Transmission lines in Rajasthan— Northern Grid, and (3) Transmission lines 'n Madhya Pradesh—Southern Grid.

HAFIZ MOHAMMAD IBRAHIM: Sir, this is a list received by the Centre from the State Governments. Whatever information I have received I have furnished to the hon. Member. But if there is any other information that the hon. Member wants, I can make enquiries from the State Governments about that also and inform the hon. Member about it.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, हम आपका संरक्षण चाहेंगे क्योंकि हमें यहां पर जानकारी आपके माध्यम से प्राप्त होती है और हमें पूरी जानकारी प्राप्त करने का मंत्रियों से अधिकार है। अगर माननीय मंत्री जी उत्तर देना चाहते थे तो यह अत्यन्त आवश्यक है कि वह इस बात को देखते कि जब वे पूरा इस्टीमेटेड कास्ट बतलाने को तैयार हैं तो उन्हें पूरक प्रश्न का उत्तर देने के लिए भी तैयार रहना चाहिये था।

MR. CHAIRMAN: He says that he has given to you the information which he got from the States. If there is any other information to be obtained, he will enquire from the States and communicate it to the hon. Member concerned.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : मेरा निवेदन यह है कि हम आप से संरक्षण चाहते हैं और मेरा यह अधिकार है कि मैं पूरक प्रश्न पूछ सकता हूं। माननीय मंत्री जी को चाहिये था कि उत्तर देने से पहले सारा इस्टीमेट मंगवाते और सारी इंफारमेशन या तो अपने पास रखते या फिर वे अगली तारीख के लिए जवाब को रखते।

HAFIZ MOHAMMAD IBRAHIM: I have already done that, Sir. I have a long list which covers 2£ pages which has been laid on the Table of the House. If there is any omission therein, Which is not in my knowledge, if it is brought to my notice by the hon. Member I can ask only the State Government concerned.

SHRI N. C. KASLIWAL: May I know, Sir, what is the total amount of loan that has been advanced to the State in respect cf this project?

HAFIZ MOHAMMAD IBRAHIM: The amount of loans so far advanced?

SHUI N. C. KASLIWAL: Yes.

MR. CHAIRMAN: How mu'jh loan has been advanced till now—thfett is what he wants to know.

HAFIZ MOHAMMAD IBRAHIM: I want notice. I said that the figure is not available at present.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि अभी तक किस किस सरकार का कितना कितना रुपया खर्च हो चुका है ?

HAFIZ MOHAMMAD IBRAHIM: The entire amount spent so far is not given here. Only half and half is given.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : कितनी सिंचाई की क्षमता उसकी हो चुकी है और एक्चुअल कितनी सिंचाई हो रही है ?

HAFIZ MOHAMMAD IBRAHIM: It will come to the extent of 14 lakh acres.

'नारू' की बीमारी

*१५८. श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) देश के किन किन क्षेत्रों में जनता 'नारू' की बीमारी से पीड़ित रहती है; और

(ख) उक्त बीमारी के उन्मूलन के लिये सरकार क्या योजना अपनाना चाहती है ?

tt'NARu' DISEASE

*158. SHRI V. M. CHORDIA: Will the Minister of HEALTH be pleased to state:

(a) the names of the regions in the country where people suffer from the 'Naru' disease; and

(b) what plan Government propose to adopt to eradicate the said disease?]

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना का एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) नारू अथवा गिनी-वर्म का संक्रमण राजस्थान के बहुत से क्षेत्रों में, महाराष्ट्र, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, मद्रास, मध्य प्रदेश, मैसूर, पंजाब और जम्मू और काश्मीर के कुछ भागों में तथा पाण्डिचेरी के अलकुप्पोम गांव में व्याप्त है।

(ख) नारू अथवा गिनी-वर्म पर नियंत्रण तथा उसका उन्मूलन विशेषतया तभी हो सकता है जब सुरक्षित पेय जल प्रदाय की व्यवस्था [ ] English translation. किये जायें